



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 23 दिसम्बर, 2002/2 पौष, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला, 171002, 23 दिसम्बर, 2002.

संख्या एल० एल० आर०-डी० (6)-23/2002. लैज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 20-12-2002 को प्रख्यापित

हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश संख्यांक 4) को संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र, (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अध्यादेश, 2002

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

हिमाचल प्रदेश राज्य में सह-चिकित्सीय परिषद् की स्थापना करने और सह-चिकित्सीय व्यवसायियों और संस्थानों द्वारा व्यवसाय को विनियमित करने के लिए उपबन्ध करने हेतु अध्यादेश।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

(1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् अध्यादेश, 2002 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. इस अध्यादेश में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएं।

(क) “अनुमोदित संस्था” से, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र या विश्वविद्यालय द्वारा संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त कोई ऐसी संस्था अभिप्रेत है जिसमें कोई व्यक्ति, उसे कोई सह-चिकित्सीय अर्हता प्रदान करने से पूर्व, कोई प्रशिक्षण, यदि कोई उसके अध्ययन पाठ्यक्रम द्वारा अपेक्षित हो, प्राप्त कर सकेगा;

(ख) “परिषद्” से, इस अध्यादेश की धारा 3 के अधीन स्थापित सह-चिकित्सीय परिषद्, अभिप्रेत है ;

(ग) “राजपत्र” से, राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है;

(घ) “पैरा क्लिनिकल स्थापन” से, युक्तियों और उपस्करों की सहायता से पैथोलोजिकल, बैक्टीरी-औरलोजिकल जेनेरिक, रेडियोलोजिकल, बायोलोजिकल अन्वेषणों और अन्य नैदानिक सेवाओं की पूर्ति के लिए एक स्वतन्त्र सत्ता के रूप में या किसी स्थापन जैसे कि अस्पताल, नर्सिंग होम, पोलि क्लिनिक, सेनिटोरियम, प्रसूति गृह, प्रतिरक्षण या टीकाकरण क्लिनिक, औषधालय, विशेष रूप जहाँ शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार, अशक्त, घायल या विकलांग व्यक्ति का रोगी के रूप में ईलाज संप्रेक्षण या देखभाल या बाह्यरोगी के रूप में ईलाज किया जाता है, के भाग के रूप में स्थापित स्थान अभिप्रेत है ;

(ड) "सह-चिकित्सीय" से, सह-चिकित्सीय विषय में अर्हित कोई भी व्यक्ति (परसोनल) अभिप्रेत है जो—

- | | |
|---|-------------|
| (i) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1956 की धारा 2 के खण्ड (च) के अर्थ के अन्तर्गत चिकित्सा ; या | 1956 का 102 |
| (ii) हिमाचल प्रदेश होम्योपैथी व्यवसायी अधिनियम, 1979 की धारा 2 के खण्ड (4) के अर्थ के अन्तर्गत होम्योपैथी में चिकित्सा ; या | 1980 का 3 |
| (iii) हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक और यूनानी व्यवसायी अधिनियम, 1968 की धारा 2 के खण्ड (ड) और (ज) के अर्थ के अन्तर्गत क्रमशः आयुर्वेदिक पद्धति और यूनानी पद्धति की चिकित्सा के अध्यापन तथा व्यवसाय में सहायता करते हों ; | 1968 का 21 |

- (च) "सह-चिकित्सीय संस्थान" से, भारत के भीतर या बाहर, ऐसा संस्थान अभिप्रेत है जो सह-चिकित्सा में उपाधियाँ, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र या अनुज्ञप्ति प्रदान करता है ;
- (छ) "सह-चिकित्सीय अर्हता" से, इस अध्यादेश से संलग्न अनुसूची में वर्णित सह-चिकित्सीय शिक्षा सम्बन्धी अर्हता अभिप्रेत है ;
- (ज) "विहित" से, इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (झ) "अध्यक्ष" से, परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;
- (ञ) "मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हता" से, विधि द्वारा स्थापित किसी विश्व विद्यालय द्वारा या इस निमित्त राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्था द्वारा किसी भी सह-चिकित्सीय अर्हता में दी गई कोई उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाणपत्र अभिप्रेत है ;
- (ट) "रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सीय व्यवसायी" से, इस अध्यादेश की धारा 38 के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (ठ) "रजिस्ट्रार" से परिषद् द्वारा, इस अध्यादेश की धारा 32 के अधीन, नियुक्त रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;
- (ड) "अनुसूची" से, इस अध्यादेश से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (ढ) "राज्य सरकार" से, हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ; और
- (ण) "राज्य रजिस्टर" से, इस अध्यादेश के अधीन रखा गया रजिस्टर अभिप्रेत है तथा पद "रजिस्ट्रीकृत" और "रजिस्ट्रीकरण" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ।

परिषद् की
स्थापना ।

3. (1) राज्य सरकार, यथाशक्य शीघ्र राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, ऐसी तारीख से, जो उस में विनिर्दिष्ट की जाए, सह-चिकित्सीय परिषद् की स्थापना करेगी ।

(2) परिषद् हिमाचल प्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् के नाम से एक निगमित निकाय होगी और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और तथा उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और उसे जंगम तथा स्थावर दोनों प्रकार की सम्पत्ति अर्जित, धारण और व्ययन करने और संविदा करने और इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए आवश्यक अन्य समस्त

बातें करने की शक्ति होगी, और वह उक्त नाम द्वारा वाद ला सकेगी और उसी नाम से उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा ।

4. (1) परिषद् निम्नलिखित सदस्य से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

परिषद् का
गठन ।

(i) पदेन सदस्य

(क) निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, हिमाचल प्रदेश	अध्यक्ष
(ख) निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश	उपाध्यक्ष
(ग) निदेशक, दन्त स्वास्थ्य सेवाएं, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
(घ) निदेशक, आयुर्वेद, हिमाचल प्रदेश	सदस्य
(ङ) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला तथा डा0 राजेन्द्र प्रसाद, राजकीय आयुर्विज्ञान टांडा के आर्यबीडक्स के विभागाध्यक्ष	सदस्य
(च) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला तथा डा0 राजेन्द्र प्रसाद, राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, टांडा के माईक्रोबायलॉजी विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष	सदस्य
(छ) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला तथा डा0 राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा के वायोकेमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष	सदस्य
(ज) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला तथा डा0 राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा के पैथोलॉजिकल विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष	सदस्य
(झ) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला तथा डा0 राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा के रेडियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष	सदस्य
(ञ) इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय, शिमला तथा डा0 राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा के फिजियोथरेपी विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष	सदस्य

(ii) गैर सरकार सदस्य

(ट) रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सीय व्यवसायियों के पांच निर्वाचित सदस्य और दो सह-चिकित्सीय संस्थानों से तथा ऐसी रीति में जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए, अपने में से निर्वाचित किए जाने वाले पैरा-क्लिनिकल संस्थान से दो सदस्य :

परन्तु इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने के पश्चात् प्रथम बार परिषद् का गठन होने की दशा में इस प्रवर्ग के सदस्यों को निर्वाचित सदस्यों के पद ग्रहण करने तक राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

(iii) रजिस्ट्रार, परिषद् का सचिव होगा

(2) कोई भी व्यक्ति एक समय में, सदस्य के रूप में, एक से अधिक हैसियत में सेवा नहीं करेगा।

सदस्यता के लिए निरर्हताएं।

5. (1) कोई भी व्यक्ति गैर-सरकारी सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि:-

- (क) वह भारत का नागरिक नहीं है ; या
- (ख) वह अनुमोचित दिवालिया है ; या
- (ग) वह विकृतचित्त का है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे इस प्रकार घोषित कर दिया गया है ; या
- (घ) वह नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया गया है ; या
- (ङ) वह परिषद् का कर्मचारी है और उसे वेतन या मानदेय द्वारा पारिश्रमिक दिया जाता है ; या
- (च) उसका नाम, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन बनाए गए राज्य रजिस्टर में से या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या सङ्घ-चिकित्सीय व्यवसायी के रजिस्टर में से, हटा दिया गया हो।

परिषद् के गैर सदस्यों को पदावधि।

6. (1) इस अध्यादेश में अन्यथा उपबन्धित के बिना, गैर सरकारी सदस्य परिषद की प्रथम बैठक की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि का अवसान होते हुए भी, पद छोड़ने वाला सदस्य, यथास्थिति कार्यालय में बना रहेगा जब तक कि नया सदस्य नामनिर्दिष्ट या निर्वाचित नहीं हो जाता और पद ग्रहण नहीं कर लेता।

गैर सरकारी सदस्यों द्वारा त्यागपत्र।

7. परिषद् का कोई गैर-सरकारी सदस्य अध्यक्ष को सम्बोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा और त्याग पत्र, अध्यक्ष द्वारा उसके त्यागपत्र की स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होगा।

परिषद् के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए नियोगताएं।

8. (1) यदि परिषद् का कोई गैर-सरकारी सदस्य, अपनी पदावधि की कालावधि के दौरान--

- (क) परिषद् की लगातार तीन बैठकों से, परिषद् की अनुमति के बिना, स्वयं अनुपस्थित रहता है ; या
- (ख) लगातार बारह मास से अधिक की अवधि के लिए विदेश में रहा है ; या
- (ग) धारा 5 में विनिर्दिष्ट निरर्हताओं में से किसी निरर्हता से ग्रस्त हो जाता है ; या
- (घ) तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत चिकित्सीय व्यवसायी नहीं रहता है ;
- (ङ) तो परिषद् उसका पद रिक्त घोषित करेगी :

परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई घोषणा तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि परिषद् के सम्बन्धित सदस्य को सुनवाई का व्यक्तिगत अवसर न दे दिया गया हो।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी घोषणा से व्यथित कोई और सरकारी सदस्य, ऐसी घोषणा की तारीख से 90 दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

9. यदि परिषद् के किसी गैर-सरकारी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या वह पद त्याग देता है या अन्यथा सदस्य नहीं रहता है, तो रिक्तियां यथाशक्य शीघ्र, निर्वाचन द्वारा भरी जाएंगी और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति, उसे सदस्य, जिस के स्थान पर वह सदस्य बना है, की अनवसित पदावधि के लिए पद धारण करेगा।

आकस्मिक
रिक्तियों का
भरा जाना।

10. (1) परिषद्, ऐसे समय, तारीख और स्थान पर बैठक करेगी जैसा अध्यक्ष नियत करें।

बैठक का
बुलाया
जाना।

(2) अध्यक्ष, जब-जब वह उचित समझे, विशेष बैठक बुला सकेगा और वह परिषद् के कम से कम 8 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अध्यादेश की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर ऐसा करने के लिए बाध्य होगा।

(3) प्रत्येक बैठक की सूचना उसमें उसका समय तथा स्थान और बैठक में किए जाने वाले काम-काज को विनिर्दिष्ट करते हुए साधारण बैठक के ठीक 15 दिन पूर्व और किसी विशेष बैठक के ठीक 7 दिन पूर्व प्रत्येक सदस्य को प्रेषित की जाएगी।

(4) बैठक में, उससे सम्बन्धित सूचना में विनिर्दिष्ट कामकाज से भिन्न कोई भी कामकाज अध्यक्ष की अनुज्ञा के सिवाए नहीं किया जाएगा।

(5) प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्यों द्वारा चुने गए किसी अन्य सदस्य द्वारा की जाएगी।

(6) परिषद् की कोई भी बैठक, परिषद् के उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से समय-समय पर, उसी दिन बाद के समय तक या किसी अन्य तारीख तक के लिए स्थगित की जा सकेगी किन्तु स्थगित बैठक में छोड़े गए कामकाज से भिन्न कोई भी कामकाज ऐसी बैठक में नहीं किया जाएगा। परिषद् के कार्यालय में या उस बैठक के स्थान पर जिस में बैठक को उस दिन स्थगित किया गया है चिपकायी गई स्थगन की सूचना ठीक आगामी बैठक की पर्याप्त सूचना समझी जाएगी।

(7) परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति, परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या की एक तिहाई होगी।

(8) यदि बैठक में किसी समय गणपूर्ति नहीं है तो पीठासीन प्राधिकारी उसे ऐसे समय या ऐसी तारीख के लिए, जो वह उचित समझे, स्थगित करेगा और बैठक के लिए रखे गए कामकाज को पश्चात्पूर्ति बैठकों में किया जाएगा चाहे ऐसी बैठक में गणपूर्ति हो या न हो।

(9) बैठक के लिए नियत किए गए काम काज से भिन्न कोई भी कामकाज ऐसी पश्चातवर्ती बैठकों में नहीं किया जाएगा।

(10) ऐसे स्थगन की सूचना (नोटिस) परिषद् के कार्यालय में या बैठक के स्थान पर छस दिन चिपकाई जाएगी जिस दिन को बैठक स्थगित की गई है।

बहुमत द्वारा प्रश्नों का विनिश्चय। 11. इस अध्यादेश में जैसा अन्यथा उपबन्धित है, के सिवाए परिषद् की बैठक के समक्ष लाए गए सभी प्रश्न उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मतों के बराबर रहने की दशा में बैठक की अध्यक्षता करने वाले पीठासीन प्राधिकारी को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

कार्यवाही के कार्यवृत्त। 12. (1) परिषद् की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त उस प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली पुस्तिका में अभिलिखित किए जाएंगे और उस में उपस्थित परिषद् के सदस्यों के नाम कार्यवृत्त पुस्तिका में दर्ज किए जाएंगे और उन पर पीठासीन प्राधिकारी द्वारा उसी या ठीक आगामी बैठक में पुष्टिकरण के लिए हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(2) परिषद् की प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के कार्यवृत्तों की एक प्रति उसकी पुष्टिकरण की तारीख से 10 दिनों के भीतर राज्य सरकार को अग्रेषित की जाएगी।

रिक्तियां आदि, कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं बनाएंगी। 13. परिषद् का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होंगी कि :—

(क) उस में कोई स्थान रिक्त है या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में व्यक्ति के निर्वाचन या नामनिर्देशन में कोई त्रुटि है, या ;

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

बैठक की कार्यवाही का विधिमान्य होना। 14. जब तक प्रतिकूल साबित न हो जाए, जब बैठक के कार्यवृत्तों पर इस अध्यादेश के उपबन्धों के अनुसार हस्ताक्षर कर दिए गए हों, तो परिषद् की प्रत्येक बैठक सम्यक रूप से बुलाई गई समझी जाएगी।

परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों के भत्ते। 15. परिषद् के गैर-सरकारी सदस्य ऐसे यात्रा और अन्य भत्ते प्राप्त करेंगे जैसे कि विनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

16. (1) परिषद् यदि यह आवश्यक समझे, अपनी बैठक सह-चिकित्सा, (पैरा मैडिसन) में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को, किसी विषय पर उसके विचारों को सुनने के लिए, आमंत्रित कर सकेगी और ऐसे व्यक्ति को, विषय पर चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु परिषद् की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

सह चिकित्सा (पैरा मैडिसन) में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले किसी भी व्यक्ति को आमन्त्रित करने की परिषद् की शक्ति।

(2) आमन्त्रित ऐसे भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा जैसे कि परिषद् के गैर सरकारी सदस्यों को अनुज्ञेय है।

17. (1) परिषद्, समय-समय पर, और ऐसी कालावधि के लिए अपने सदस्यों की ऐसी संख्या को मिलाकर जैसी कि वह उचित समझे, एक समिति नियुक्त कर सकेगी, और इस अध्यादेश के अधीन किसी विषय को, उस पर जांच और रिपोर्ट करने के लिए या राय प्राप्त करने के लिए, समिति को निर्दिष्ट कर सकेगी।

समिति की नियुक्ति।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त समिति अपनी प्रथम बैठक में अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष निर्वाचित करेगी।

(3) ऐसी समिति की नियुक्ति का ढंग, ऐसी समिति की बैठकों का बुलाया जाना और उनका आयोजन किया जाना तथा ऐसी समिति के कारबार का संचालन ऐसा होगा जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए।

18. (1) इस अध्यादेश तथा तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्याधीन रहते हुए, परिषद् ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कृत्यों का पालन करेगी जो वह इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य।

(2) विशिष्टतया और पूर्वागामी उपबन्ध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् की शक्तियाँ और कृत्य निम्नलिखित होंगे :—

- (क) सह-चिकित्सीय व्यवसायियों का राज्य रजिस्टर बनाए रखना ;
- (ख) रजिस्ट्रार के किसी भी विनिश्चय के विरुद्ध अपीलों की ऐसी रीति में जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए, सुनवाई करना या उनका विनिश्चय करना ;
- (ग) रजिस्ट्रीकृत सह चिकित्सीय व्यवसायियों के वृत्तिक आवरणों को विनियमित करने के लिए विनियमों द्वारा नैतिक आचार संहिता विहित करना ;
- (घ) किसी रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सीय व्यवसायी की भर्त्सना करना, राज्य रजिस्टर में से नाम निलम्बित कर देना या हटा देना, या उसके विरुद्ध ऐसी अन्य अनुशासनिक कारवाई करना जैसी कि परिषद् की राय में आवश्यक या समीचीन हो ;
- (ङ) किसी भी सदस्य को परिषद् की लगातार तीन बैठकों से उसे अनुपस्थित रहने की अनुमति देना ;

- (च) नए सह-चिकित्सीय विषयों की स्थापना में नई पद्धतियाँ, अनुसंधान और विकास का उन्नयन करना ;
- (छ) सह-चिकित्सीय शिक्षा का उन्नयन करने के लिए स्कीमें बनाना ;
- (ज) सह-चिकित्सीय शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा की आयुर्वेदिक पद्धति के बीच प्रभावी सम्बन्धों का उन्नयन करना और इन विषयों में अनुसंधान और विकास का उन्नयन करना ;
- (झ) पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्या, शारीरिक तथा अनुदेशात्मक सुविधाएँ, कर्मचारिवृद्ध पैटरन, कर्मचारिवृद्ध अर्हताएँ, गुणवत्ता अनुदेश, निर्धारण तथा परीक्षाओं के मानक और स्तर अधिकथित करना ;
- (ञ) अध्यापन एवं अन्य फीसों को प्रभारित करने के लिए मानक तथा मार्ग-दर्शक सिद्धांत नियत करना ;
- (ट) शिक्षा के क्षेत्र में किसी सह-चिकित्सीय निकाय या संस्था को चार्टर प्रदान करने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सलाह देना ;
- (ठ) सह-चिकित्सीय संस्थाओं और सह-चिकित्सीय शिक्षा देने वाले विश्व विद्यालयों में छात्रों के प्रवेश के लिए मार्गदर्शन करना ;
- (ड) किसी सह-चिकित्सीय संस्था का निरीक्षण करना या निरीक्षण करवाना ;
- (ढ) परीक्षा का संचालन करने हेतु बोर्ड का गठन/प्राधिकृत करना और स्तर की एकरूपता बनाए रखना ;
- (ण) पैरा-क्लिनिकल स्थापना रजिस्ट्रीकृत करना ;
- (त) पैरा-क्लिनिकल स्थापनों की स्थापना हेतु न्यूनतम स्तरमान विहित करना ;
- (थ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो नियमों द्वारा विहित किए जाएं ; और
- (द) धारा 4 की उप-धारा (1) के मद (ii) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन का संचालन ।

नए सह-चिकित्सीय संस्थान के लिए अनुज्ञा ।

19. (1) इस अध्यादेश में किसी बात के होते हुए भी ;

- (क) कोई व्यक्ति सह-चिकित्सीय संस्था की स्थापना नहीं करेगा ; और
- (ख) कोई भी सह-चिकित्सीय संस्था, इस धारा के उपबन्धों के अनुसार अभि-प्राप्त राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय :—

(i) कोई नया या उच्चर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नहीं खोलेगा जो ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के किसी छात्र को कोई मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय संस्था अर्हता प्रदान किए जाने के लिए अर्हित होने के लिए समर्थ बनाएँ ; या

(ii) किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पद “व्यक्ति” के अन्तर्गत कोई विश्व-विद्यालय या न्यास है किन्तु इसके अन्तर्गत राज्य सरकार नहीं है।

(2) प्रत्येक व्यक्ति या सह-चिकित्सीय संस्था, उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, उप-धारा (3) के उपबन्धों के अनुसार परिषद् को एक स्कीम प्रस्तुत करेगा ।

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट स्कीम ऐसे प्रारूप में होगी और उसमें ऐसी विशिष्टियाँ अन्तर्निहित होंगी और ऐसी फीस सहित ऐसी रीति से प्रस्तुत की जाएंगी जैसी विहित की जाएं।

(4) परिषद् द्वारा उप-धारा (2) के अधीन स्कीम की प्राप्ति पर परिषद्, सम्बन्धित व्यक्ति या सह-चिकित्सीय संस्था से ऐसी अन्य विशिष्टियाँ जो वह आवश्यक समझे, अभिप्राप्त कर सकेगी और तत्पश्चात् वह:-

- (क) यदि स्कीम त्रुटिपूर्ण है, और उसमें कोई आवश्यक विशिष्टियाँ नहीं दी गई हैं, तो सम्बन्धित व्यक्ति या संस्था को लिखित अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दे सकेगी और ऐसा व्यक्ति या सह-चिकित्सीय संस्था, परिषद् द्वारा निर्दिष्ट त्रुटियों को, यदि कोई हों, सुधार सकेगा; और
- (ख) उप-धारा (8) में निर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए, स्कीम पर विचार कर सकेगी और स्कीम को, अपनी सिफारिशों सहित, राज्य सरकार को प्रस्तुत कर सकेगी।

(5) राज्य सरकार, उप-धारा (4) के अधीन स्कीम पर और परिषद् की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् और जहाँ आवश्यक हो वहाँ सम्बन्धित व्यक्ति या संस्था से ऐसी अन्य विशिष्टियाँ, जो वह आवश्यक समझे, अभिप्राप्त करने के पश्चात् और उप-धारा (1) में निर्दिष्ट बातों को ध्यान में रखते हुए, स्कीम का या तो ऐसी शर्तों के साथ, यदि कोई हों, जो वह आवश्यक समझे अनुमोदन या अननुमोदन कर सकेगी और ऐसा कोई अनुमोदन उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञा होगी :

परन्तु किसी स्कीम का सम्बन्धित व्यक्ति या संस्थान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना, राज्य सरकार द्वारा अननुमोदन नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस उप-धारा की कोई बात, किसी व्यक्ति या सह-चिकित्सीय संस्था को, जिसकी स्कीम राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं की गई है, नई स्कीम प्रस्तुत करने से निवारित नहीं करेगी और इस धारा के उपबन्ध ऐसी स्कीम को ऐसे लागू होंगे मानों ऐसी स्कीम उप-धारा (2) के अधीन पहली बार प्रस्तुत की गई हो।

(6) जहाँ उप-धारा (2) के अधीन राज्य सरकार को स्कीम के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा पारित कोई आदेश, स्कीम को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या संस्था को संसूचित नहीं किया गया है, वहाँ ऐसी स्कीम, उस प्रारूप में जिसमें वह प्रस्तुत की गई थी, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई समझी जाएगी और तदनुसार, उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित राज्य सरकार की अनुज्ञा भी दे दी गई समझी जाएगी।

(7) उप-धारा (6) में निर्दिष्ट समय सीमा की संगणना करने में परिषद् द्वारा या राज्य सरकार द्वारा मांगी गई किन्हीं विशिष्टियों को देने में स्कीम को प्रस्तुत करने वाले सम्बन्धित व्यक्ति या संस्था द्वारा लिए गए समय को अपवर्जित कर दिया जाएगा।

(8) परिषद्, उप-धारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन अपनी सिफारिशें करते समय और राज्य सरकार, उप-धारा (5) के अधीन स्कीम का अनुमोदन या

अनुमोदन करने वाला आदेश पारित करते समय निम्नलिखित बातों का सम्यक् ध्यान रखेगी, अर्थात् :—

- (क) क्या प्रस्तावित सह-चिकित्सीय संस्था या विद्यमान पाठ्यक्रम खोलना चाहती है इस अध्यादेश सह-चिकित्सीय संस्था जो नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण की धारा 26 के अधीन परिषद् द्वारा यथा विहित सह-चिकित्सीय शिक्षा का न्यूनतम स्तर प्रदान करने की स्थिति में होगी ;
- (ख) क्या उस व्यक्ति के पास, जो किसी सह-चिकित्सीय संस्था की स्थापना करना चाहता या किसी विद्यमान सह-चिकित्सीय संस्था के पास, जो नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम खोलना चाहता है या अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना चाहती है, पर्याप्त वित्तीय साधन है ;
- (ग) क्या सह-चिकित्सीय संस्था का उचित कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिए या नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण संचालित करने या वर्धित प्रवेश क्षमता के आवासन के लिए कर्मचारिवृंद, उपस्कर, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाओं की बाबत आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है या स्कीम में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर व्यवस्था कर दी जाएगी ;
- (घ) क्या ऐसे छात्रों की, जिनके ऐसे सह-चिकित्सीय संस्था या पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उपस्थित होने की सम्भावना है या वर्धित प्रवेश क्षमता के परिणामस्वरूप छात्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त अस्पताल सुविधाओं की व्यवस्था की गई है या स्कीम में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर व्यवस्था कर दी जाएगी ;
- (ङ) क्या ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिनके पास मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हताएं हैं, ऐसे छात्रों को , जिनके ऐसे सह-चिकित्सीय संस्था या पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में उपस्थित होने की सम्भावना है, उचित प्रशिक्षण देने के लिए कोई इंतजाम किया गया है या कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ।
- (च) चिकित्सा व्यवसाय के क्षेत्र में जन शक्ति की अपेक्षा ; और
- (छ) कोई अन्य बातें (कारक) जो विहित की जाएं ।

(9) यहां राज्य सरकार इस धारा के अधीन किसी स्कीम का अनुमोदन या अनुमोदन करने वाला कोई आदेश पारित करती है, वहां उस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित व्यक्ति या सह-चिकित्सीय संस्था को संसूचित की जाएगी ।

कतिपय मामलों में सह-चिकित्सीय अर्हता की अमान्यता ।

20. जहां इस अध्यादेश के उपबन्धों के उल्लंघन में, राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोई सह-चिकित्सीय संस्था स्थापित की जाती है या कोई सह-चिकित्सीय संस्था कोई नया या उच्चतर पाठ्यक्रम आरम्भ करती है या अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करती है वहां ऐसी सह-चिकित्सीय संस्था द्वारा किसी छात्र को इस प्रकार दी गई सह-चिकित्सीय अर्हता इस अध्यादेश के प्रयोजनों के लिए मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हता नहीं होगी ।

21. यदि किसी व्यक्ति ने सह-चिकित्सीय संस्था स्थापित की है या किसी सह-चिकित्सीय संस्था ने नया या उच्चतर पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण आरम्भ किया है या प्रवेण क्षमता में वृद्धि की है तो, यथास्थिति, ऐसा व्यक्ति या सह-चिकित्सीय संस्था इस अध्यादेश के प्रारम्भ होने से एक वर्ष की अवधि के भीतर इन अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार की अनुज्ञा प्राप्त करेगी ।

कतिपय विद्यमान सह-चिकित्सीय संस्थाओं के लिए अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु समय ।

22. भारत की ऐसी कोई सह-चिकित्सीय संस्था, जो अपने द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सीय अर्हता को अनुसूची में सम्मिलित करना चाहती है, ऐसी अर्हता की मान्यता के लिए राज्य सरकार को, ऐसी आवेदन फीस के साथ, जैसी विनियम द्वारा नियत की जाए, आवेदन कर सकेगी और राज्य सरकार, परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का इस प्रकार संशोधन कर सकेगी कि उसमें ऐसी अर्हता सम्मिलित हो जाए, और ऐसी किसी अधिसूचना में यह भी निर्देश दिया जा सकेगा कि अनुसूची के अन्तिम स्तम्भ में ऐसी सह-चिकित्सीय अर्हता के सामने यह घोषित करते हुए एक प्रविष्टि को जाएगी कि वह मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हता तभी होगी जब वह किसी विनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात् अनुदत्त की जाए ।

कतिपय सह-चिकित्सीय संस्थाओं, जिनकी अर्हताएं, अनुसूची में सम्मिलित नहीं हैं, द्वारा अनुदत्त सह-चिकित्सीय अर्हता को मान्यता ।

23. भारत में प्रत्येक विश्वविद्यालय या सह-चिकित्सीय संस्था, जो मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हता देती है, ऐसी अर्हता प्राप्त करने के लिए पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और दी जाने वाली परीक्षाओं के बारे में, उस आयु के बारे में, जिसमें ऐसे पाठ्यक्रमों का पूरा किया जाना और परीक्षाओं का दिया जाना है, और ऐसी अर्हता का प्रदान किया जाना अपेक्षित है, और साधारणतया ऐसी अर्हता प्राप्त करने के लिए उपेक्षाओं के बारे में ऐसी जानकारी देगी जिसकी परिषद् समय-समय पर, अपेक्षा करे ।

पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं के सम्बन्ध में जानकारी की अपेक्षा करने की शक्ति।

24. परिषद् जब भी आवश्यक समझे, सभी सह-चिकित्सीय संस्थाओं का निरीक्षण करवा सकेगी ।

सह-चिकित्सीय संस्था का निरीक्षण ।

25. (1) यदि परिषद् को यह प्रतीत होता है कि, --

मान्यता का वापिस लिया जाना ।

(क) किसी विश्वविद्यालय या सह-चिकित्सीय संस्था में पूरे किए जाने वाले पाठ्यक्रम और दी जाने वाली परीक्षा अथवा उसके द्वारा ली गई परीक्षा में अभ्यर्थियों से अपेक्षित प्रवीणता, परिषद् द्वारा विहित स्तरों के अनुरूप नहीं है ; या

(ख) ऐसे विश्वविद्यालय या सह-चिकित्सीय संस्था में या उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या अन्य संस्था में कमचारीसर्वद उपस्कर वास-सुविधा, प्रशिक्षण और उसमें दिए जाने वाले शिक्षण और प्रशिक्षण की अन्य सुविधाएं परिषद् द्वारा विहित स्तरों के अनुरूप नहीं हैं ।

तो परिषद् मान्यता की वापसी के लिए कार्रवाई करेगी।

(2) मान्यता वापस लिए जाने से पूर्व परिषद् सह-चिकित्सीय संस्था या विश्वविद्यालय को वह अवधि विनिर्दिष्ट करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करेगी जिसके भीतर जवाब प्रस्तुत किया जाना है।

(3) जवाब की प्राप्ति पर या जहां कारण बताओ नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई जवाब प्रस्तुत न किया जाए वहां उस अवधि का अवसान होने पर परिषद् मामले में विनिश्चय करेगी।

सह-
चिकित्सीय
शिक्षा के
न्यूनतम
स्तर।

26. परिषद् भारत के विश्वविद्यालयों या सह-चिकित्सीय संस्थाओं द्वारा (स्नातकोत्तर सह-चिकित्सीय अर्हताओं से भिन्न) मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हता प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षित सह-चिकित्सीय शिक्षा के न्यूनतम स्तर विहित कर सकेगी।

पैरा-
क्लिनिकल
स्थापनों का
रजिस्ट्रीकरण।

27. कोई भी व्यक्ति इस अध्यादेश के अधीन इस रूप में रजिस्ट्रीकृत किए बिना और इस अध्यादेश के अधीन स्वीकृत रजिस्ट्रीकरण के निबन्धनों के अनुसार के सिवाए नहीं खोलेगा, रखेगा या चलाएगा :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात ऐसे पैरा-क्लिनिकल स्थापन को जो इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख को विद्यमान है, ऐसी तारीख से छः मास की अवधि के लिए या जहां आवेदन इस अवधि के भीतर धारा 28 के उपबन्धों के अनुसार किया है तब तक जब तक आवेदन का निपटारा न कर दिया जाए, लागू नहीं होगी।

रजिस्ट्रीकरण
के लिए
आवेदन।

28. (1) प्रत्येक व्यक्ति जो पैरा-क्लिनिकल स्थापन को चलाने का आशय रखता हो, इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर पैरा-क्लिनिकल स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए परिषद् को आवेदन करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पैरा-क्लिनिकल स्थापन के रजिस्ट्रीकरण या उप-धारा (6) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन में ऐसी विशिष्टियां होंगी और ऐसी फीस संलग्न होगी जैसी विनियमनों द्वारा विहित की जाए।

(3) यदि परिषद् का समाधान को हो जाए कि आवेदक और पैरा-क्लिनिकल स्थापन ऐसे निबन्धन और शर्तों को विहित की जाएं, पूरी करता है, तो आवेदक और ऐसे पैरा क्लिनिकल स्थापन को रजिस्टर करेगी और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसे प्रारूप में जैसा विहित किया जाए, रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र प्रदान करेगी।

(4) परिषद् आवेदन को नामंजूर कर सकेगी यदि उसका समाधान हो जाता है आवेदक या पैरा-क्लिनिकल स्थापन उप-धारा (3) के अधीन विहित शर्तों को पूरा नहीं करता है और प्रत्येक मामले में जहां आवेदन नामंजूर किया गया है, उसके कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित किया जाएगा।

(5) धारा 29 के उपबन्धों के अध्याधीन, इस धारा के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्रवृत्त होगा और इसके उप-धारा (3) के अधीन प्रदान किए जाने की

तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा जब तक कि इसे इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन पूर्वतर रद्द नहीं कर दिया जाता ।

(6) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन, उप-धारा (3) के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र की वैधता के अवसान से पूर्व छः माह की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

29. परिषद्, धारा 28 के अधीन पैरा-क्लिनिकल स्थापन को रजिस्टर किए जाने के पश्चात् किसी भी समय ऐसा रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकती है यदि इसका समाधान हो जाता है कि :—

रजिस्ट्रीकरण का रद्द-करण ।

- (i) रजिस्ट्रीकरण के निर्बंधन और शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है ; या
- (ii) व्यक्ति, जिसके नाम से पैरा-क्लिनिकल स्थापन रजिस्ट्रीकृत किया गया हो को इस अध्यादेश के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जा चुका है ; या
- (iii) विधिक व्यक्ति सहित कोई अन्य व्यक्ति, जिसे इस अध्यादेश के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा चुका है किसी अन्य विधिक व्यक्ति या अन्य पैरा-क्लिनिकल स्थापन के साथ सहयुक्त है ।

30. (1) प्रत्येक पैरा क्लिनिकल स्थापन के भवनों, स्थान, सुविधा, उपस्कर और जनशक्ति के ऐसे न्यूनतम मानक होंगे जैसे परिषद् द्वारा विनियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

पैरा-क्लिनिकल स्थापन के न्यूनतम मानक ।

(2) प्रत्येक पैरा क्लिनिकल स्थापन अनुसेवित या दाखिल या उपचारित सभी व्यक्तियों का विहित रीति में अभिलेख बनाएगा तथा बनाए रखेगा और ऐसे अभिलेख या उनके उद्धरण, परिषद् या राज्य सरकार के प्राधिकृत तकनीकी अधिकारी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की पंक्ति से नीचे अधिकारी, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो के मांग करने पर उपलब्ध करवाए जाएंगे ।

(3) मांग किए जाने पर रोगी या उसके कुटुंब के किसी सदस्य अथवा रोगी द्वारा इस प्रभाव में विनिर्दिष्ट रूप में प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को, पैरा क्लिनिकल स्थापन द्वारा दाखिले, परामर्श, परीक्षण, निदान और उपचार के अभिलेख की अधि-प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाई जाएगी ।

31. (1) परिषद् या राज्य सरकार का कोई प्राधिकृत तकनीकी अधिकारी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, साधारण या विशेष आदेश जैसे राज्य सरकार द्वारा किए जाएं के अध्याधीन किसी परिसर, जिसके लिए परिषद् या ऐसे प्राधिकृत राज्य सरकार के अधिकारी के विश्वास करने के युक्तियुक्त हेतुक हो कि इनको पैरा क्लिनिकल स्थापन के प्रयोजन हेतु प्रयोग किया गया है या किया जा रहा है, में प्रवेश और निरीक्षण कर सकेगा ।

पैरा-क्लिनिकल स्थापन का निरीक्षण ।

(2) यदि उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत परिषद् या अधिकारी के विश्वास करने के हेतुक है कि कोई वस्तु या वस्तुओं की श्रेणी अथवा कोई अभिलेख इस

अध्यादेश के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए अभिग्रहण किये जाने हों तो वह किसी वस्तु या अभिलेख, जो उसकी राय में इस अध्यादेश के अधीन किसी कार्यवाही को चलाने के लिए उपयोगी और सुसंगत है, का अभिग्रहण कर सकेगा और अभिग्रहित वस्तुओं या अभिलेख के लिए रसीद देगा।

(3) तलाशी और अभिग्रहण से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबन्ध, (1974 का जहाँ तक समुचित हो सके इस अध्यादेश के अधीन की गई ऐसी प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण को लागू होंगे। 2)

परिषद् का
रजिस्ट्रार,
और अन्य
अधिकारी
तथा सेवक।

32. (1) परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से एक रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी वो परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(2) परिषद् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऐसे अन्य अधिकारियों एवं सेवकों को नियोजित कर सकेगी, जैसे वह इस अध्यादेश के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे।

(3) रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों और सेवकों की अर्हताएं, सेवा की शर्तें और वेतनमान ऐसे होंगे जैसे परिषद्, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से विनियमों द्वारा अबधारित करे।

(4) परिषद् द्वारा इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया रजिस्ट्रार या कोई अन्य अधिकारी या सेवक भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा। (1860 का 45)

रजिस्ट्रार
के कर्तव्य।

33. (1) रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अध्यादेश के उपबन्धों और परिषद् द्वारा दिए गए किसी आदेश के अनुसार राज्य रजिस्टर रखे और बनाए रखे, उसे ऐसी रीति में, जैसी कि समय-समय पर विनियमों द्वारा विहित की जाए पुनरीक्षित करे, उसे राजपत्र में प्रकाशित करे और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे, जिनकी इस अध्यादेश और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अधीन उसके द्वारा निर्वहन किए जाने की उससे अपेक्षा हो या की जाए।

(2) रजिस्ट्रार का यह सुनिश्चित करने के लिए यह कर्तव्य होगा कि राज्य रजिस्टर यथासम्भव सभी समयों पर सही है और वह उसमें, समय-समय पर रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सीय व्यवसायियों के पते या उनकी अर्हताओं में हुए किसी सारवान परिवर्तन को, प्रविष्ट कर सकेगा।

(3) रजिस्ट्रार, राज्य रजिस्टर में से उस रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सीय व्यवसायी का नाम हटा सकेगा जिसकी मृत्यु हो जाती है या जिसका नाम राज्य रजिस्टर में से परिषद् द्वारा हटाए जाने के लिए उसे निर्देशित किया गया हो या जो सह-चिकित्सीय व्यवसायी नहीं रह गया हो।

(4) रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सीय व्यवसायी द्वारा आवेदन करने पर, यदि परिषद् का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यवसायी ने व्यवसाय करना बन्द नहीं किया है तो परिषद् रजिस्ट्रार को निर्देश दे सकेगी कि ऐसे व्यवसायी का नाम राज्य रजिस्टर में पुनः प्रत्यावर्तित करे और रजिस्ट्रार ऐसे निर्देश का अनुपालन करेगा।

34. परिषद् एक निधि स्थापित करेगी जो परिषद् की निधि कहलाएगी जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा :— परिषद् की निधियाँ ।

- (क) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा कोई अभिदाय या अनुदान ;
- (ख) फीस और जुर्मानों से हुई आय सहित परिषद् की समस्त स्त्रोतों से आय ;
- (ग) न्यास, दान, विन्यास और अन्य अनुदान यदि कोई हो ; और
- (घ) परिषद् द्वारा प्राप्त समस्त अन्य धन राशियाँ ।

35. परिषद् की निधि निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपयोजित होगी :—

- (क) उन ऋणों के प्रतिदाय के लिए जो परिषद् द्वारा इस अध्यादेश और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रयोजनों के लिए, उपगत किए गए हो ;
- (ख) किसी ऐसे वाद या किन्हीं ऐसी विधिक कार्यवाहियों के व्ययों के लिए जिन में परिषद् एक पक्षकार हो ;
- (ग) परिषद् के अधिकारियों और सेवकों के वेतन और भत्तों के संदाय के लिए ;
- (घ) परिषद् के पदाधिकारियों को भत्तों के संदाय के लिए ;
- (ङ) किन्हीं ऐसे व्ययों के संदाय के लिए जो इस अध्यादेश के और तद्धीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में परिषद् द्वारा उपगत किए गए हों ; और
- (च) गृह-चिकित्सीय व्यवसाय के सामान्य हित में परिषद् द्वारा घोषित गृह-चिकित्सीय शिक्षा, अनुसन्धान और प्रशिक्षण के उन्नयन और विकास के लिए उपगत अन्य व्यय ।

उद्देश्य जिन के लिए परिषद् की निधि उप-योजित की जाएगी ।

36. (1) परिषद् के लेखों को, ऐसी तारीख से पूर्व और ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति में जैसी कि विनियमों द्वारा विहित की जाए, तैयार किया जाएगा ।

लेख और संपरीक्षा ।

(2) परिषद् के लेखों की संपरीक्षा रजिस्ट्रीकृत चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा की जाएगी और चार्टर्ड एकाउन्टेंट की संपरीक्षा (आडिट) फीस ऐसी होगी जैसी परिषद् द्वारा, विनियमों द्वारा विहित की जाए ।

(3) जैसे ही परिषद् के लेखों की संपरीक्षा हो जाए, परिषद् उसकी एक प्रति, उस पर निदेशक चिकित्सा शिक्षा की रिपोर्ट की प्रति सहित राज्य सरकार को ऐसी रीति में जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए, भेजेगी ।

37. (1) रजिस्ट्रार ऐसे, प्ररूप में, जो कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए वित्तीय वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए, बजट तैयार करवाएगा और इसे परिषद् के समक्ष ऐसे समय पर, ऐसी रीति में रखवाएगा, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए ।

बजट ।

(2) उस बैठक, जिसमें बजट पास किया गया हो, की तारीख के 15 दिन के भीतर, इसे राज्य सरकार को अर्पणित किया जाएगा ।

(3) यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि उसको इस प्रकार अग्रेषित किए गए बजट के उपबन्ध, इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो वह बजट को, ऐसे संशोधनों (उपान्तरणों) के लिए, जैसे राज्य सरकार द्वारा सुझाए जाएं परिषद् को वापस करेगी।

(4) परिषद् ऐसी रकमों को, जैसी आवश्यक हो, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष और लघु शीर्षों को पुनः विनियोजित करने के लिए सक्षम होगी।

(5) परिषद्, जब भी अपेक्षित हो, ऐसे प्ररूप में, जैसे विनियमों द्वारा विहित किया जाए, अनुपूरक बजट पारित कर सकेगी और उप-धारा (2), (3) और (4) के उपबन्ध, ऐसे अनुपूरक बजट को लागू होंगे।

रजिस्ट्रीकरण
नवीकरण
और राज्य
रजिस्टर।

38. (1) किसी भी व्यक्ति को चिकित्सीय व्यवसायी के रूप में राज्य रजिस्टर में, तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने मान्यता प्राप्त अर्हता प्राप्त न कर ली हो और ऐसी फीस, जैसी नियमों द्वारा विहित की जाए, का संदाय न कर दिया हो और भिन्न-भिन्न अर्हताओं के लिए भिन्न फीस विहित की जा सकेगी, किन्तु यह एक हजार रुपये से अधिक नहीं होगी। और रजिस्ट्रीकरण 3 वर्ष के लिए विधिमाम्य होगा।

(2) परिषद् सह-चिकित्सीय व्यवसायियों का एक राज्य रजिस्टर ऐसे प्ररूप में रखाएगी जैसा कि विनियमों द्वारा विहित किया जाए।

(3) ऐसा रजिस्टर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अर्थ के अन्तर्गत लोक दस्तावेज समझा जाएगा। (1872 का 1)

(4) उप-धारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत चिकित्सीय व्यवसायी प्रत्येक 3 वर्षों के पश्चात्, ऐसी फीस के संदाय पर, जैसी विहित की जाए, अपने रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करवाएगा।

कैपिटेशन
फीस चन्दा
(डोनेशन)
इत्यादि
वसूल करना
प्रतिपिद्ध।

39. कोई भी व्यक्ति या सह-चिकित्सा संस्थान जो किसी सह-चिकित्सीय संस्थान का भारसाधक है या उसके प्रबन्धन का उत्तरदायी है :-

(क) प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई चन्दा (डोनेशन), दान या अन्य संदाय (चाहे किसी भी नाम से प्रकाशित जाए) चाहे नकद या माल के रूप में हो, या कोई राशि कैपिटेशन फीस के रूप में स्वीकार नहीं करेगा; या

(ख) परिषद् द्वारा प्रस्तुत (संस्तुत) फीसों के मापमान से अधिक कोई फीस या राशि स्वीकार नहीं करेगा।

राज्य
रजिस्टर में
प्रविष्टि
किए जाने
का प्रतिषेध
करने या
उसमें से
उसके हटाए
जाने का
आदेश देने
की परिषद्
की शक्ति।

40. परिषद्, रजिस्ट्रार से निदेश प्राप्त होने पर, या अन्यथा अध्यादेश द्वारा रजिस्टर में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम प्रविष्टि किए जाने का प्रतिषेध कर सकेगी या उस रजिस्टर में से किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हटाए जाने का आदेश दे सकेगी :-

(क) जिसे किसी दण्ड न्यायालय ने किसी ऐसे अपराध के लिए कारावास से दण्डादिष्ट किया है जिसमें नैतिक अद्यमता अन्तर्गुह्य है; या

(ख) जिसे परिषद् ने, जांच के पश्चात् परिषद् की बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा वृत्तिक अवचार में दोषी पाया हो :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर दिए बिना, पारित नहीं किया जाएगा।

41. (1) परिषद्, सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर देने के पश्चात् यह आदेश दे सकेगी कि राज्य रजिस्टर में की गई कोई ऐसी प्रविष्टि, जो परिषद् की राय में, कपटपूर्वक या गलती से की गई है या करवा दी गई है रद्द कर दी जाए या संशोधित की जाए।

राज्य
रजिस्टर में
परिवर्तन।

(2) परिषद् किसी रजिस्ट्रीकृत सह-चिकित्सीय व्यवसायी का नाम राज्य रजिस्टर में से सदैव के लिए या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हटाए जाने का निदेश उन्हीं कारणों से दे सकेगी जिनके आधार पर परिषद् द्वारा रजिस्ट्रीकरण धारा 40 के अधीन प्रतिषेध किया जा सकेगा।

(3) परिषद्, यह निदेश दे सकेगी कि उप-धारा (2) के अधीन हटाया गया नाम, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, जिन्हें परिषद् अधिरोपित करना उचित समझे, अध्याधीन रहते हुए पुनः प्रत्यावर्तित किया जाए।

42. इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए परिषद् या धारा 17 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त कोई समिति, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अर्थ के अन्तर्गत न्यायालय समझी जाएगी, और वह लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 के अधीन नियुक्त आयुक्त की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी, और ऐसी जांच यथाशक्य लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 की धारा 5 और धारा 8 से 20 तक के उपबन्धों के अनुसार संचालित की जाएगी।

जांचों में
प्रक्रिया।

43. ऐसा कोई भी व्यक्ति;

(क) जिस का राज्य रजिस्टर में नामांकन के लिए आवेदन धारा 38 या 41 के अधीन नामंजूर कर दिया गया हो; या

(ख) जिसके नाम की प्रविष्टि राज्य रजिस्टर में धारा 40 के अधीन प्रतिषिद्ध कर दी गई हो; या

(ग) जिस का नाम राज्य रजिस्टर से हटा दिया गया हो;

परिषद्
के आदेश
के विरुद्ध
अपील।

यथास्थिति, इस प्रकार नामंजूर किए जाने, प्रतिषेध किए जाने या हटाए जाने के आदेश के नब्बे दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

44. (1) इस अध्यादेश में यथा उपबन्धित से अन्यथा के सिवाए, कोई भी व्यक्ति राज्य के भीतर सह-चिकित्सीय व्यवसायी के रूप में व्यवसाय नहीं करेगा या स्वयं को, व्यक्तिगत लाभ के लिए, चाहे प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः इस रूप में व्यपदेशित नहीं करेगा कि वह अभ्यासतः सह-चिकित्सीय व्यवसाय करता है।

इस अध्या-
देश में यथा
उपबन्धित
के सिवाय
व्यवसाय
करने का
प्रतिषेध।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वह कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।

45. जहां परिषद् का, स्वप्रेरणा से या प्राप्त किसी आभ्यवेदन पर या अन्यथा समाधान हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति या सह-चिकित्सीय संस्था ने इस अध्यादेश या तदधीन बनाए गए या जारी नियमों या विनियमों या आदेशों के सभी या किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो यह राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से और

कतिपय
मामलों में
उपाधि प्रदान
करने पर
प्रतिषेध।

1872 का
1
1908 का
5
1850 का
37

ऐसी शर्तों के अध्याधीन जिन्हें वह अधिरोपित करना उचित समझे :-

(क) प्रथम उल्लंघन की दशा में संबंधित सह-चिकित्सीय संस्था को, ऐसे विद्यार्थियों को, जिनके संबंध में उल्लंघन किया गया है, किसी विश्वविद्यालय या चिकित्सा (आयुर्विज्ञान) संस्था में कोई परीक्षा देने के लिए उपस्थित (प्रस्तुत) करने के लिए प्रतिषिद्ध कर सकेगी जो ऐसे विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता प्राप्त करने के हेतु अर्हित करने के लिए समर्थ बनाए; और

(ख) किसी दूसरे या पश्चात्तवर्ती उल्लंघन इस अध्यादेश के अधीन ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जैसी वह आवश्यक समझे और इसके अन्तर्गत संबंधित सह-चिकित्सीय संस्था को विद्यार्थियों का कोई और प्रवेश प्रतिषिद्ध करने के लिए कार्रवाई करना भी है :

परन्तु यह कि परिषद द्वारा ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबंधित सह-चिकित्सीय संस्था और विद्यार्थियों को सुनवाई का युक्ति-युक्त अवसर प्रदान न कर दिया गया हो ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन परिषद द्वारा पारित किसी भी आदेश की प्रति संबंधित सह-चिकित्सीय संस्था और विद्यार्थी को संसूचित की जाएगी और साथ-साथ इसकी एक प्रति संबंधित विश्वविद्यालय या सह-चिकित्सीय संस्था को अग्रेषित की जाएगी ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उप-धारा (1) के अधीन परिषद द्वारा पारित आदेश और उप-धारा (2) के अधीन विश्व-विद्यालय या सह-चिकित्सीय संस्था को संसूचित आदेश अन्तिम होगा और तथाकथित विश्वविद्यालय और सह-चिकित्सीय संस्था पर आबद्धकर होगा ।

(4) उप-धारा (2) के अधीन विश्वविद्यालय या सह-चिकित्सीय संस्था को संसूचित आदेश, किए जाने की तारीख के पश्चात् हुई परीक्षा या अन्य टैस्ट के आधार पर ऐसी सह-चिकित्सीय संस्था के किसी विद्यार्थी को प्रदत्त कोई सह-चिकित्सीय अर्हता इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए, ऐसे विद्यार्थी के सम्बद्ध में मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय अर्हता नहीं रहेगी ।

(5) जहां परिषद् द्वारा किसी सह-चिकित्सीय संस्था के सम्बन्ध में उप-धारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित किया गया है तो राज्य सरकार स्वप्रेरणा से और प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर, यदि उसकी यह राय है कि ऐसा करना ऐसे सह-चिकित्सीय संस्था विद्यार्थियों के हित में आवश्यक और समीचीन है, ऐसे पग उठाएगी जिन्हें वह ऐसे सह-चिकित्सीय संस्था में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों के हित के संरक्षण के लिये आवश्यक समझे ।

अपराध और शास्तियां । 46. (1) इस अध्यादेश या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस अध्यादेश की धारा 19 में यथा अग्रेषित सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना स्थापित सह-चिकित्सीय संस्था या चलाए गए पाठ्यक्रम या प्रवेश क्षमता में को राज्य सरकार सहित किसी भी प्राधिकरण द्वारा नियमित नहीं किया जाएगा ।

(2) जो कोई भी उप-धारा (1) के उपबन्धों वा उल्लंघन करेगा धारा 19 के अधीन किसी भी अनुज्ञा के लिए पात्र नहीं होगा । यह निरहता उस तारीख से, जिसको कि धारा 19 का उल्लंघन सिद्ध हो जाता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगा ।

(3) यदि कोई अनुमोदित या मान्यता प्राप्त सह-चिकित्सीय संस्था राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना पाठ्यक्रम (कोर्स) आरम्भ करती है और विद्यार्थियों को प्रवेश देती है तो ऐसी संस्था की, अनुमोदित प्रवेश क्षमता को उसके सभी अनुमोदित पाठ्यक्रमों में 25 प्रतिशत कम कर दिया जायेगा और ऐसी संस्था को आगामी शैक्षणिक वर्ष के विरुद्ध किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश देने के लिए अनुज्ञात नहीं दिया जाएगा।

47. (1) जो कोई धारा, 19, 20, 21, 27 या 39 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह इस अध्यादेश की धारा 45 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से जो पांच लाख रुपये तक का हो सकेगा किन्तु पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

धारा 19,
20, 21,
27 या
39 के
उल्लंघन
के लिए
आस्ति।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन दोष सिद्ध की गई है, न्यायालय उस उप-धारा के अधीन कोई दण्ड देने के अतिरिक्त, लिखित आदेश द्वारा, सह-चिकित्सीय संस्था या किसी अन्य सिद्ध दोष व्यक्ति से इस प्रकार अधिक वसूल (संग्रहित) की गई राशि को उस व्यक्ति को, जिससे यह वसूल की गई है, ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विहित की जा सकेगी, लौटाने की अपेक्षा कर सकेगा।

48. (1) जहां इस अध्यादेश के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस अपराध के किये जाने के समय उस कम्पनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दंडित किये जाने के भागी होंगे:

कम्पनियों
द्वारा
अपराध।

परन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अध्यादेश के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी, यथास्थिति की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है तो वह उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण:—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म, संस्था, सोसाइटी, न्यास या न्यासियों का अन्य संगम है; और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में “निदेशक” से उस फर्म का व्यक्ति अभिप्रेत है।

प्रमाण-पत्र को बैँमानी से उपयोग में लाने के लिए शास्ति।

49. कोई भी व्यक्ति जो :—

- (क) इस अध्यादेश के अधीन दिए गए किसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का बैँमानी से उपयोग करता है ; या
- (ख) किसी मिथ्या या कपटपूर्ण घोषणा, प्रमाण पत्र या व्यपदेशन को, चाहे वह लिखित में हो या अन्यथा, करके या पेश करके अथवा कराकर या पेश कराकर इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करता है या प्राप्त करने का प्रयत्न करता है ; या
- (ग) इस अध्यादेश के उपबन्धों के अधीन जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित किसी विषय में कोई भी मिथ्या व्यपदेशन जानबूझकर करता है या करवाता है,—

दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा किन्तु जो पांच हजार रुपए से कम न होगा या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

परिषद् द्वारा दी जाने वाली जानकारी।

50. परिषद् ऐसी रिपोर्ट अपने ऐसे कार्यवृत्तों की प्रतिलिपियां, अपने ऐसे लेखों की संक्षिप्तियां (एक्सट्रैक्ट्स) और ऐसी अन्य जानकारी राज्य सरकार को देगी जिनकी राज्य सरकार अपेक्षा करें।

अपराध का संज्ञान।

51. (1) कोई भी न्यायालय इस अध्यादेश के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, रजिस्ट्रार या परिषद् द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के लिखित में किए गए परिवाद पर करने के सिवाय न करेगा।

(2) प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

राज्य सरकार द्वारा नियन्त्रण।

52. यदि राज्य सरकार को, किसी भी समय, यह प्रतीत होता है कि परिषद्, उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में असफल रही है या उसने उनका अतिरेक या दुरुपयोग किया है या वह इस अध्यादेश द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों में से किसी कर्तव्य का पालन करने में असफल रही है, तो राज्य सरकार, यदि वह यह विचार करती है कि ऐसी असफलता, अतिरेक या दुरुपयोग गम्भीर स्वरूप का है, उसे ऐसी असफलता, अतिरेक या दुरुपयोग का, ऐसी अवधि के भीतर, जैसी कि सूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपचार किए जाने की अपेक्षा करते हुए, उनकी विशिष्टियां परिषद् को अधिसूचित कर सकेगी और यदि परिषद्, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी असफलता, अतिरेक या दुरुपयोग का उपचार करने में असफल रहती है तो राज्य सरकार परिषद् को विघटित कर सकेगी और परिषद् की समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन, इस निमित्त सरकार द्वारा, आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा छः मास से अनाधिक अवधि तक करवा सकेगी और नयी परिषद् को अस्तित्व में लाने के लिए कदम उठाएगी।

53. (1) राज्य सरकार, इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकेगी।

नियम
बनाने की
शक्ति।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य-शीघ्र, विधानसभा के समक्ष, जब वह कुल 14 दिन की अवधि से अन्यून सत्र में हों, के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या दो से अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि सत्र के अवसान के पूर्व जिसमें यह इस तरह रखा गया था यह शीघ्र बाद के सत्र में, विधान सभा नियम में कोई उपांतरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो नियम उसके पश्चात् केवल ऐसे उपान्तरित रूप में, यथास्थिति, प्रभावी होगा, या निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि-मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

54. (1) परिषद् राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से और धारा 4 के अधीन बनाए नियमों के अधीन रहते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगी और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित के लिए उपबन्ध हो सकेंगे :—

विनियम
बनाने की
शक्ति।

- (क) परिषद् की सम्पत्ति का प्रबन्ध और उसके लेखों का अनुरक्षण और उनकी संपरीक्षा ;
- (ख) परिषद् के सदस्यों के निर्वाचन की रीति ;
- (ग) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य ;
- (घ) समितियों की नियुक्ति का ढंग, ऐसी समितियों की बैठकों का बुलाया जाना और उनका आयोजित किया जाना और ऐसी समितियों के कारबार का संचालन ;
- (ङ) परिषद् के गैर-सरकारी सदस्यों को देय यात्रा और अन्य भत्ते ;
- (च) धारा 18 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) के अधीन रजिस्ट्रार के विनिश्चय के कारण हुई अपीलों को सुनने और उन्हें विनिश्चित करने की रीति ;
- (छ) धारा 18 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन वृत्तिक आचरण को विनियमित करने के लिए नीति विषयक संहिता ;
- (ज) धारा 32 की उप-धारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों और सेवकों की अर्हताएं, सेवा की शर्तें और वेतनमान ;
- (झ) धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य रजिस्ट्रार के पुनर्निरीक्षण की रीति ; और ,
- (ञ) धारा 34 की उप-धारा (2) के अधीन राज्य रजिस्ट्रार का प्ररूप।

(2) राज्य सरकार, अनुमोदन के लिए, विनियमों को प्राप्त करने पर, उन्हें किसी उपांतरण के बिना या उपांतरणों सहित, जैसे वह उचित समझे, अनुमोदित कर सकेगी या उन्हें पुनर्विचार के लिए परिषद् को लौटा सकेगी।

अनुसूची

सह-चिकित्सीय अर्हताएं
[धारा 2 (घ) देखें]

1. भौतिक, चिकित्सा/व्यवसायिक चिकित्सा पाठ्यक्रम ।
2. वाक्शक्ति चिकित्सा पाठ्यक्रम ।
3. श्रण्य शास्त्रीय ।
4. प्रयोगशाला तकनीशियन (विभिन्न प्रकार के) ।
5. किरण (एक्सरे) तकनीशियन/रेडियोग्राफर ।
6. वी० सी० जी० तकनीशियन ।
7. साइटों तकनीशियन ।
8. आर्थो तकनीशियन ।
9. नमूनों कक्ष तकनीशियन (मोल्ड रूम तकनीशियन) ।
10. गामा कैमरा तकनीशियन ।
11. आर्थोटिक तकनीशियन ।
12. आपटरेमेट्रिस्ट ।
13. आर्थोटिक और कांटेक्ट लैन्स ।
14. ई० सी० जी० तकनीशियन ।
15. आल्ट्रासाउंड ।
16. एन्जियोग्राफी ।
17. शल्यक्रिया कक्ष तकनीशियन ।
18. मानव पोषण में उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र ।
19. डायलिसिस चिकित्सा तकनीशियन ।
20. इन्सुलेषन चिकित्सा तकनीशियन ।
21. स्वास्थ्य निरीक्षक पाठ्यक्रम ।
22. अस्पताल चिकित्सा अभिलेख विज्ञान ।
23. कम्पाउंडर (एलोपैथी), आयुर्वेदिक, युनानी तथा होम्योपैथी ।
24. बायोकेमी चिकित्सा पद्धति का कम्पाउन्डर ।
25. शपनिक जीव रसायन (करोनिकल बायो केमिस्ट्री) में डिप्लोमा ।
26. सूक्ष्म जीव रसायन (माइक्रोबायोलॉजी) ।
27. पैथोलॉजी (व्याधिकी) ।
28. ओपटोमेट्रिक (रिफ्रैक्शनलिस्ट) ।
29. सह-चिकित्सीय नेत्र रोग सहायक (आप्टालमिक) ।
30. परफ्युजनिस्ट/कार्डियक सर्जरी तकनीशियन ।
31. केथ प्रयोगशाला तकनीशियन ।
32. डेंटल हाईजिनिस्ट/डेंटल मेकनिक ।
33. मेल हेल्थ वर्कर (पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता) ।
34. फीमेल हेल्थ वर्कर (महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता) ।

शिमला:

तारीख ————— 2002

सूरज भान,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ।

सचिव विधि,
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

ANNEXURE-A

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

H. P. Ordinance No. 4 of 2002.

THE HIMACHAL PRADESH PARAMEDICAL COUNCIL
ORDINANCE, 2002

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Fifty-third Year of the Republic of India.

AN

ORDINANCE

to provide for the establishment of Paramedical Council in the State of Himachal Pradesh and to regulate the practice by paramedical practitioners and institutions.

WHEREAS the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action.

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following ordinance:—

1. (1) This Ordinance may be called the Himachal Pradesh Paramedical Council Ordinance, 2002.

Short title
and com-
mencement.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, in the Official Gazette, appoint.

2. In this Act, unless the context otherwise requires, —

Definiti-
ons.

(a) "approved institution" means a hospital, health centre or other such institution recognised by a University as an institution in which a person may undergo the training, if any, required by his course of study before the award of any paramedical qualification to him ;

(b) "Council" means Paramedical Council established under section 3 of this Ordinance ;

(c) "Official Gazette" means the Rajpatra, Himachal Pradesh ;

(d) "Para-clinical establishment" means a place catering to pathological, bacteriological, genetic radiological, biological investigations or other diagnostic services with the aid and assistance of devices and equipments, established as an independent entity or part of an establishment such as a hospital, nursing home, polyclinic sanatorium, maternity home, immunisation or vaccination clinics, dispensary, special camps where physically or mentally sick, infirm, injured or disabled person is admitted

as a patient for treatment, observation or care or seen as out patient.

- (e) "paramedical" means any personnel qualified in paramedical subject and who helps in teaching or practice of—
 - (i) medicine within the meaning of clause (f) of section 2 of the Indian Medical Council Act, 1956 ; or 102 of 1956
 - (ii) medicine in Homoeopathy within the meaning of clause 4 of section 2 of the Himachal Pradesh Homoeopathic Practitioners Act, 1979; or 3 of 1980
 - (iii) medicine in Ayurvedic system and Unani System within the meaning of clause (e) and (h) respectively of section 2 of the Himachal Pradesh Ayurvedic and Unani Practitioners Act, 1968 ; 27 of 1968
- (f) "paramedical institution" means any institution, within or outside India, which grants degrees, diplomas, certificates or licence in paramedical;
- (g) "paramedical qualification" means the qualification relating to paramedical education, mentioned in the Schedule appended to this Ordinance ;
- (h) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Ordinance ;
- (i) "President" means the President of the Council :
- (j) "recognised paramedical qualification" means a degree, diploma or certificate in any paramedical qualification, granted by any University established by law or any other institution recognised by the State Government in this behalf ;
- (k) "registered paramedical practitioner" means a person registered as such under section 38 of this Ordinance ;
- (l) "Registrar" means the Registrar appointed by the Council under section 32 of this Ordinance ;
- (m) "Schedule" means a Schedule appended to this Ordinance ;
- (n) "State Government" means Government of Himachal Pradesh ; and
- (o) "State Register" means a register maintained under this Ordinance and expression "registered" and "registration" shall be construed accordingly.

(2) The Council shall be a body corporate by the name of the Himachal Pradesh Paramedical Council, and shall have perpetual succession and a common seal, with power to acquire, hold and dispose of property both movable and immovable and to contract and to do all other things necessary for the purpose of this Ordinance, and may be the said name sue and be sued.

4. (1) The Council shall consist of the following members, namely:—

Constitution of Council.

(i) EX-OFFICIO MEMBERS :

- | | |
|--|------------------------|
| (a) Director Medical Education, Himachal Pradesh | <i>President.</i> |
| (b) Director Health Services, Himachal Pradesh | <i>Vice-President.</i> |
| (c) Director Dental Health Services, Himachal Pradesh | <i>Member</i> |
| (d) Director Ayurveda, Himachal Pradesh | <i>Member.</i> |
| (e) Heads of Department of Orthopaedics Indira Gandhi Medical College, Shimla and Dr. Rajindra Prasad Government Medical College Tanda. | <i>Members.</i> |
| (f) Professor and Heads of Department Microbiology Indira Gandhi Medical College Shimla and Dr. Rajindra Prasad Government Medical College, Tanda. | <i>Members.</i> |
| (g) Professor and Heads of Department Bio-Chemistry Indira Gandhi Medical College, Shimla and Dr. Rajindra Prasad Government Medical College Tanda. | <i>Members.</i> |
| (h) Professor and Heads of Department Pathology Indira Gandhi Medical College, Shimla and Dr. Rajindra Prasad Government Medical College Tanda. | <i>Members.</i> |
| (i) Professor and Heads of Department Radiology Indira Gandhi Medical College, Shimla and Dr. Rajindra Prasad Government Medical College, Tanda. | <i>Members.</i> |
| (j) Professor and Heads of Department Physiotherapy Indira Gandhi Medical College, Shimla and Dr. Rajindra Prasad Government Medical College, Tanda. | <i>Members.</i> |

(ii) NON-OFFICIAL MEMBERS :

Five elected members of the registered paramedical practitioners and two from paramedical institutions and two from

para clinical establishment to be elected from amongst themselves in such manner as may be prescribed by regulation :

provided that in the case of constitution of the Council for the first time after the commencement of this Ordinance, the members of this category shall be nominated by the State Government till assumption of office by the elected members.

(iii) Registrar shall be the Secretary of the Council.

(2) No person shall at the same time serve as a member in more than one capacity.

Disqualifications for membership.

5. A person shall be disqualified for being a non-official member if—

(a) he is not a citizen of India ; or

(b) he is an undischarged insolvent ; or

(c) he is of unsound mind and stands so declared by a competent court ; or

(d) he has been sentenced for an offence involving moral turpitude ; or

(e) he is an employee of the Council and is remunerated by salary or honorarium ; or

(f) his name has been removed from the State Register, or from the register of registered medical or paramedical practitioner maintained under any Act for the time being in force.

Term of office of non-official member of the Council.

6. (1) Save as otherwise provided in this Ordinance, non-official members shall hold office for a term of three years from the date of first meeting of the Council.

(2) Notwithstanding the expiration of the term specified under subsection (1), an outgoing member shall continue in office until a new member is nominated or elected, as the case may be, and assumes office.

Resignation by non-official member.

7. Any non-official member of the Council may resign from his office by a letter addressed to the President and the resignation shall take effect from the date of acceptance of his resignation by the President.

Disabilities for continuing as the member of the Council.

8. (1) If any non-official member of the Council during the period of his office—

(a) absents himself from three consecutive meeting of the Council without the permission of the Council ; or

(b) remained abroad for a period exceeding twelve consecutive months ; or

- (c) becomes subject to any of the disqualifications specified in section 5 ; or
- (d) ceases to be registered paramedical practitioner under any Act, for the time being in force ;

the Council shall declare his office as vacant :

Provided that no declaration shall be made under this sub-section unless a reasonable opportunity of being heard is given to the concerned member of the Council.

(2) Any non-official member aggrieved by a declaration under sub-section (1) may prefer an appeal to the State Government within ninety days from the date of such declaration and the decision of the State Government thereon shall be final.

9. If a non-official member of the Council dies or resigns, or otherwise ceases to be a member, the vacancies shall be filled, as soon as may be, by election, and the person so elected shall hold office for the unexpired term of office of the member in whose place he becomes a member.

Filling
of casual
vacancies.

10. The Council shall meet at such time, date and place, as the President may fix.

Convening
of
meeting.

(2) The President may, whenever he thinks fit call a special meeting, and shall be bound to do so within two weeks of the receipt of written requisition, signed by not less than eight members of the Council.

(3) The notice of every meeting specifying the time and place thereof and the business to be transacted thereat, shall be despatched to every member fifteen clear days before an ordinary meeting and seven clear days before a special meeting.

(4) No business other than that specified in the notice relating thereto, shall be transacted at a meeting except with the permission of the chair.

(5) Every meeting shall be presided over by the President and in his absence by the Vice-President and in the absence of both by any other member chosen by the members present.

(6) Any meeting of the Council may, with the consent of the majority of the members of the Council present, be adjourned from time to time, to a later hour on the same day or to any other date, but no business other than left over at the adjourned meeting shall be transacted at such meeting. A notice of adjournment pasted in the office of the Council or at the place of meeting, on the day on which the meeting is adjourned, shall be deemed sufficient notice of the next ensuing meeting.

(7) The quorum for a meeting of the Council shall be one third of the total number of members of the Council.

(8) If at any time in a meeting there is no quorum, the presiding authority shall adjourn it to such time or date as it thinks fit and the business set down for the meeting shall be transacted at the subsequent meeting, whether at such meeting there is a quorum or not.

(9) No business other than the business fixed for the meeting, shall be transacted at such subsequent meeting.

(10) A notice of such adjournment shall be affixed in the office of the Council or at the place of meeting, on the day on which the meeting is adjourned.

Decision of questions by majority of votes.

11. Save as otherwise provided in this Ordinance, all questions brought before any meeting of the Council, shall be decided by a majority of votes of the members present and in case votes being equal the presiding authority at the meeting shall have a second or casting vote.

Minutes of Proceeding.

12. (1) The minutes of proceedings of each meeting of the Council shall be recorded in a book to be kept for the purpose and the names of the members of the Council present thereat shall be entered in the minute book ; and shall be signed in confirmation by the Presiding Authority at the same or next meeting.

(2) A copy of the minutes of proceedings of each meeting of the Council shall be forwarded to the State Government within ten days from the date of its confirmation.

Vacancies etc. not to invalidate proceedings.

13. No act or proceedings of the Council shall be invalid merely by reasons of—

(a) any vacancy therein, or any defect in the constitution thereof ; or

(b) any defect in the election or nomination of a person as a member thereof ; or

(c) any irregularity in its procedure not affecting merits of the case,

Proceeding of meeting to be valid.

14. Until the contrary is proved, every meeting of the Council shall be deemed to have been duly convened when the minutes of the meeting have been signed in accordance with the provisions of this Ordinance.

Allowances of the non-official members of the Council.

15. The non official members of the Council shall receive such travelling and other allowances as may be prescribed by regulations.

Power of Council to invite any person having knowledge or experience in paramedicine.

16. (1) The Council may, if it thinks necessary, invite any person having special knowledge or experience in paramedicine to its meeting, to hear his views on the subject and such person shall have right to take part in the discussion on the subject but shall not have the right to vote in the meeting of the Council.

(2) The invitee shall be entitled to receive such allowances as are admissible to the non-official members of the Council.

17. (1) The Council may appoint, from time to time and for such period, a committee consisting of such number of its members as it may think fit and may refer to such committee for enquiry and report or for opinion any matter under this Ordinance.

Appoint-
ment of
committee.

(2) The committee appointed under sub-section (1) shall at its first meeting elect one of its member to be its Chairman.

(3) The mode of appointment of such committee, the summoning and holding of meetings and the conduct of business of such committee shall be such as may be prescribed by regulations.

18. (1) Subject to the provisions of this Ordinance and the rules made thereunder, the Council shall exercise such powers and perform such functions as may be necessary for carrying out the purposes of this Ordinance.

Powers and
functions
of the
Council.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing provision, the powers and functions of the Council shall be,—

- (a) to maintain the State Register of paramedical practitioner ;
- (b) to hear and decide appeals from the decision of the Registrar in such manner as may be prescribed by regulations ;
- (c) to prescribe by regulations a code of ethics for regulating the professional conduct of registered paramedical practitioners ;
- (d) to reprimand a registered paramedical practitioner, or to suspend or remove the name from the State Register, or to take such other disciplinary action against him, as may, in the opinion of the Council, be necessary or expedient ;
- (e) to permit any member to be absent from three consecutive meetings of the Council ;
- (f) to promote innovations, research and development in establishment of new paramedical subjects ;
- (g) to formulate schemes for promoting paramedical education ;
- (h) to promote an effective link between Paramedical Education, Medical Education and Ayurvedic System of Medicine and to promote research and development in these subjects ;
- (i) to lay down norms and standards for courses, curricula, physical and instructional facilities, staff pattern, staff qualifications, quality instructions, assessment, examinations and continuing medical education ;
- (j) to fix norms and guidelines for charging tuition and other fees ;
- (k) to advise the State Government in respect of grant of charter to any paramedical body or institution in the field of education ;

- (l) to provide guidelines for admission of student of paramedical institutions and Universities imparting paramedical education ;
- (m) to inspect or cause to be inspected any paramedical institution ;
- (n) to constitute or authorise a Board for conducting the examination and to maintain uniformity of standard ;
- (o) to register para-clinical establishments ;
- (p) to prescribe minimum standards for the establishment of para clinical establishments ;
- (q) to perform such other functions as may be prescribed ; and
- (r) to conduct the election of members under item (ii) of sub-section (1) of section 4.

Permission
for establish-
ment of new
paramedical
institution.

19. (1) Notwithstanding anything contained in this Ordinance;—

(a) no person shall establish a paramedical institution ; and

(b) no paramedical institution shall—

(i) open a new or higher course of study or training which would enable a student of such course or training to qualify himself for the award of any recognised paramedical qualification ; or

(ii) increase its admission capacity in any course of study or training ;

except with the previous permission of the State Government obtained in accordance with the provisions of this section.

Explanation.—For the purposes of this section, the expression “person” includes any University or a trust but does not include the State Government.

(2) Every person or paramedical institution shall, for the purpose of obtaining permission under sub-section (1), submit to the Council a scheme in accordance with the provisions of sub-section (3).

(3) The scheme referred to in sub-section (2) shall be in such form, contain such particulars, preferred in such manner and accompanied with such fee, as may be prescribed.

(4) On receipt of a scheme by the Council under sub-section (2), the Council may obtain such other particulars as may be considered necessary by it from the person or the paramedical institution concerned and thereafter, it may—

(a) if the scheme is defective and does not contain any necessary particulars, give a reasonable opportunity to the person or insti-

tution concerned for making a written representation and it shall be open to such person or paramedical institution to rectify the defects, if any, specified by the Council ; and

- (b) consider the scheme, having regard to the factors referred to in sub-section (8), and submit the scheme together with its recommendations thereon to the State Government.

(5) The State Government may, after considering the scheme and the recommendations of the Council under sub-section (4) and after obtaining, where necessary, such other particulars as may be considered necessary by it from the person or institution concerned, and having regard to the factor referred to in sub-section (1), either approve (with such conditions, if any, as it may consider necessary) or disapprove the scheme and any such approval shall be a permission under sub-section (1) :

Provided that no scheme shall be disapproved by the State Government except after giving the person or institution concerned a reasonable opportunity of being heard :

Provided further that nothing in this sub-section shall prevent any person or paramedical institution whose scheme has not been approved by the State Government to submit a fresh scheme and the provisions of this section shall apply to such scheme as if such scheme has been submitted for the first time under sub-section (2).

(6) Where, within a period of one year from the date of submission of the scheme to the Council under sub-section (2), no order passed by the State Government has communicated to the person or institution submitting the scheme, such scheme shall be deemed to have been approved by the State Government in the form in which it had been submitted to the Council and accordingly, the permission of the State Government required under sub-section (1) shall also be deemed to have been granted.

(7) In computing the time-limit specified in sub-section (6), the time taken by the person or institution concerned submitting the scheme in furnishing any particulars called for by the Council, or by the State Government, shall be excluded.

(8) The Council, while making its recommendations under clause (b) of sub-section (4) and the State Government while passing an order, either approving or disapproving the scheme under sub-section (5), shall have due regard to the following factors, namely:—

(a) whether the proposed paramedical institution or the existing paramedical institution making to open a new or higher course of study or training, would be in a position to offer the minimum standards of paramedical education as prescribed by the Council under section 26 of this Ordinance ;

(b) whether the person seeking to establish a paramedical institution or the existing paramedical institution seeking to open a new or higher course of study or training or to increase its admission capacity has adequate financial resources ;

- (c) whether necessary facilities in respect of staff, equipment, training and other facilities to ensure proper functioning of the paramedical institution or conducting the new course of study or training or accommodating the increased admission capacity have been provided or would be provided within the time-limit specified in the scheme ;
 - (d) whether adequate hospital facilities, having regard to the number of students likely to attend such paramedical institution or course of study or training or as a result of the increased admission capacity, have been provided or would be provided within the time-limit specified in the scheme ;
 - (e) whether any arrangement has been made or programme drawn to impart proper training to students likely to attend such paramedical institution or course of study or training by persons having the recognised Paramedical qualifications ;
 - (f) the requirement of manpower in the field of practice of medicine ; and
 - (g) any other factors as may be prescribed.
- (9) Where the State Government passes an order either approving or disapproving a scheme under this section a copy of the order shall be communicated to the persons or paramedical institution concerned.

Non-recognition of paramedical qualification in certain cases.

20. Where any paramedical institution is established or any paramedical institution opens a new or higher course of study or increases its admission capacity without the previous permission of the State Government in contravention of the provisions of this Ordinance, paramedical qualification so given to any student by such paramedical institution, shall not be recognised paramedical qualification for the purpose of this Ordinance.

Time for seeking permission for certain existing paramedical institution.

21. If any person has established a paramedical institution or any paramedical institution has opened a new or higher course of study or training or increases the admission capacity, such person or paramedical institution, as the case may be, shall seek within a period of one year from the commencement of this Ordinance, the permission of State Government under the provisions of this Ordinance.

Recognition of paramedical qualification granted by certain paramedical institutions whose qualifications are not included in the Schedule.

22. Any paramedical institution in India, which desires a paramedical qualification granted by it, to be included in the Schedule, may apply to the State Government with such application fee as may be fixed by regulation to have such qualification recognised and the State Government, after consulting the Council, may by notification in the Official Gazette, amend the Schedule as to include such qualification therein, and any such notification may also direct that an entry shall be made in the last column of Schedule against such paramedical qualification declaring that it shall be a recognised paramedical qualification only when granted after specified date.

23. Every University or paramedical institution in India which grants a recognised paramedical qualification, shall furnish such information as the Council, may, from time to time, require as to the courses of study and examinations to be undergone in order to obtain such qualification, as to the ages at which such courses of study and examinations are required to be undergone and such qualifications conferred and generally as to the requisites for obtaining such qualification.

Power to require information as to courses of study and examination.

24. The Council shall cause all paramedical institutions to be inspected as and when deemed necessary.

Inspection of paramedical institution.

25. (1) If it appears to the Council,—

Withdrawal of recognition.

- (a) that the courses of the study and examination to be undergone in or the proficiency required from candidates at any examination held by any University or paramedical institution do not conform to the standards prescribed by regulations by the Council ; or
- (b) that the staff, equipments, accommodation, training and other facilities for instruction and training provided in such University or paramedical institution or in any college or other institution affiliated to that University do not conform to the standards prescribed by regulations by the Council ;

the council shall take action for the withdrawal of recognition ;

(2) Before withdrawal of recognition, the Council shall send a show cause notice to the paramedical institution or University specifying the period within which the reply shall be submitted.

(3) On receipt of the reply or where no reply is submitted within the period specified the show cause notice then on expiry of that period the Council shall take decision in the matter.

26. The Council may prescribe by regulation the minimum standards of paramedical education required for granting recognised paramedical qualifications (other than postgraduate) paramedical qualification by the paramedical institutions in India.

Minimum Standards of paramedical education.

27. No person shall open, keep or carry on a para-clinical establishment without being registered as such under this Ordinance and except in accordance with the terms of registration granted under this Ordinance:

Registration of para-clinical establishments.

Provided that nothing in this section shall apply to a para-clinical establishment which is in existence on the date of commencement of this Ordinance for a period of six months from such date or where an application is made within that period in accordance with provisions of section 28 till such time as the application is disposed of.

28. (1) Every person intending to carry on a para-clinical establishment shall make an application to the Council for registration of the clinical establishment within a period of three months from the date of commencement of this Ordinance.

Application for registration.

(2) Every application for registration of para-clinical establishment under sub-section (1) or for renewal of the registration under sub-section (6) shall contain such particulars and shall be accompanied by such fees, as may be prescribed by regulations.

(3) The Council, if satisfied that the applicant and the para-clinical establishment fulfils such terms and conditions as may be prescribed, shall register the applicant and such para-clinical establishment shall grant him in relation to the para-clinical establishment a certificate of registration in such form as may be prescribed within a specified period.

(4) The Council may reject an application if it is satisfied that the applicant or the para-clinical establishment does not fulfil the conditions prescribed under sub-section (3) and in every case where the application is rejected, reasons therefor shall be recorded in writing.

(5) A certificate of registration issued under this section, subject to the provision of section 29, shall be in force and shall be valid for a period of five years from the date on which it is granted under sub-section (3) unless cancelled earlier as per provision of this Ordinance.

(6) An application for renewal of a registration shall be made within a period of six months before the expiry of validity of registration certificate issued under sub-section (3).

**Cancellation
of regi-
stration.**

29. At any time after a para-clinical establishment is registered under section 28, the Council, may cancel such registration if it is satisfied.—

- (i) that the terms and conditions of the registration are not being complied with ; or
- (ii) that the person in whose name the para-clinical establishment is registered, has been convicted of an offence punishable under this Ordinance ; or
- (iii) that any other person including a juristic person who has been convicted of an offence under this Ordinance is associated with another juristic person or other para-clinical establishment.

**Minimum
standards
of para-
clinical
establish-
ment.**

30. (1) Every para-clinical establishment shall have such minimum standards of buildings, space, facility, equipment and manpower as are prescribed by the Council by regulations.

(2) Every para-clinical establishment shall maintain and keep records of all persons attended or admitted or treated in the manner prescribed and such records or extracts thereof shall be made available to the Council or the authorised technical Officer of the State Government not below the Chief Medical Officer on demand.

(3) On demand, an authenticated copy of the record of admission, consultation, tests, diagnosis and treatment shall be made available by the clinical establishment to the patient or any of his family member or any other person specifically authorised by the patient to this effect.

31. (1) The Council or any authorised technical officer of the State Government, not below the rank of a Chief Medical Officer, subject to general or special order as may be made by the State Government, enter and inspect any premises which are used or for which the Council, or the officer of the State Government so authorised has reasonable cause to believe that these are being used for the purpose of para-clinical establishment.

Inspection
of para-
clinical
establish-
ment.

(2) If the Council or the officer authorised under sub-section (1) has any reason to believe that any article or class of articles or any records are liable to be seized for the contravention of the provisions of this Ordinance, he may seize any article or record which in his opinion is useful or relevant for initiating any proceeding under this Ordinance and give receipt for articles or records so seized.

(3) The provisions of the Criminal Procedure Code, 1973 relating to searches and seizures shall, as far as may be appropriate, apply to such every search or seizure made under this Ordinance.

32. (1) The Council shall, with the prior approval of the State Government, appoint a Registrar who shall act as Secretary of the Council.

Registrar
and other
officers and
servants
of the
Council.

(2) The Council may, with the prior approval of the State Government, employ such other officers and servants as it may deem necessary for carrying out the provisions of this Ordinance.

(3) The qualifications, conditions of service and pay scales of the Registrar and other officers and servants shall be such as the Council may determine by regulations, with the prior approval of the State Government.

(4) The Registrar or any other officer or servant appointed by the Council under this section shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860.

33. (1) It shall be the duty of the Registrar to keep and maintain the State Register in accordance with the provisions of this Ordinance and any order made by the Council to revise it from time to time in such manner as may be prescribed by regulations, to publish it in the Official Gazette and to discharge such other functions as are or may be required to be discharged by him under this Ordinance and the rules and regulations made thereunder.

Duties of
Registrar.

(2) It shall be the duty of the Registrar to ensure that the State Register is as far as possible correct at all time and may from time to time enter therein any material alteration in the address or qualifications of the registered paramedical practitioner.

(3) The Registrar may remove from the State Register the name of the registered paramedical practitioner who dies or whose name is directed by the Council to be removed from the State Register or who ceases to be the registered paramedical practitioner.

(4) On an application made by the registered paramedical practitioner, if the Council is satisfied that the such practitioner has not ceased to

practise. then the Council may direct the Registrar to restore the name of such practitioner in the State Register and the Registrar shall comply with such direction.

Funds of Council.

34. The Council shall establish a fund to be called the fund of the Council to which shall be credited,—

- (a) any contribution or grant by Central or State Government;
- (b) the income of the Council from all sources including income from fees and fines;
- (c) the trust, donations, endowment and other grants, if any; and
- (d) all other sums received by the Council;

Objects to which fund of the Council shall be applied.

35. The fund of the Council shall be applied,—

- (a) to the repayments of debts incurred by the Council for the purpose of this Ordinance and the rules and regulations made thereunder;
- (b) to the expenses of any suit or legal proceedings to which the Council is a party;
- (c) to the payment of salaries and allowances to the officers and servants of the Council;
- (d) to the payment of allowances to the office bearers of the Council;
- (e) to the payment of any expenses incurred by the Council in carrying out the provisions of this Ordinance and the rules and regulations made thereunder; and
- (f) to any other expenses incurred for the promotion and development of paramedical education, research and training, declared by the Council to be in the general interest of paramedical profession.

Accounts and audit.

36. (1) The accounts of the Council shall be prepared before such date and at such intervals and in such manner, as may be prescribed by regulations.

(2) The accounts of the Council shall be audited by the registered chartered accountant and the audit fee of the chartered accountant shall be such, as may be fixed by the Council, by regulations.

(3) As soon as the accounts of the Council are audited, the Council shall send a copy thereof, to the State Government, in such manner, as may be prescribed by regulations.

Budget.

37. (1) The Registrar shall cause to be prepared in such form as may be prescribed, by regulations, a budget for the financial year showing the estimated receipts and expenditure and shall cause it to be laid before the Council at such time, in such manner as may be prescribed by regulations.

(2) Within fifteen days from the date of the meeting in which the budget is passed, it shall be forwarded to the State Government.

(3) If the State Government is of the opinion that provisions of the budget so forwarded to it are not adequate for carrying out the

purposes of this Ordinance, it shall return the budget to the Council for such modification as may be suggested by the State Government.

(4) The Council shall be competent to reappropriate such amounts as may be necessary from one head to another head and minor heads.

(5) The Council, may as and when required, pass a supplementary budget in such form as may be prescribed by regulations and the provisions of sub sections (2), (3) and (4) shall apply to such supplementary budget.

38. (1) No person shall be registered on the State Register as paramedical practitioner unless he possesses a recognised qualification and has not paid such fee, as may be prescribed by rules and different fee may be prescribed for different qualifications but it shall not exceed one thousand rupees and the registration shall be valid for a period of three years.

Registration,
renewal
and State
Register.

(2) The Council shall cause to be maintained a State Register of paramedical practitioners in such form, as may be prescribed, by regulations.

1 of 1872

(3) The Register shall be deemed to be public document within the meaning of Indian Evidence Act, 1872.

(4) Every registered paramedical practitioner registered under sub-section (1) shall renew his registration after every three years on payment of such fee as may be prescribed.

39. No person or paramedical institution who is incharge of, or is responsible for the management of any paramedical institution, shall,—

Prohibition
of collection
of capitation
fee, donat-
ion etc.

(a) accept, either directly or indirectly, any donation, gift or other payment (by whatever name called), whether in cash or in kind or any amount by way of capitation fee; or

(b) receive any fee or amount in excess of scale of fees presented by the council.

40. The Council may, upon reference from the Registrar or otherwise, by order, prohibit the entry in, or order, the removal from the State Register, the name of any person,—

Power of
Council to
prohibit
entry to
or to order
removal
from State
Register.

(a) who has been sentenced by a criminal court to imprisonment for an offence which involves moral turpitude; or

(b) whom the Council, after enquiry has found guilty of professional misconduct by passing a resolution of majority of two third of the members of the Council present and voting at the meeting :

Provided that no order shall be passed under this section without giving a reasonable opportunity of being heard to the person concerned.

41. (1) The Council may, after giving the person concerned a reasonable opportunity of being heard, order that any entry in the State Register which in the opinion of the Council, has been fraudulently or incorrectly made or brought, be cancelled or amended.

Alteration
of State
Register.

(2) The Council may direct the removal for ever, or for a specified period from the State Register, the name of any registered paramedical practitioner for the same reason for which registration may be prohibited by the Council under section 40 of this Ordinance.

(3) The Council may direct that the name removed under sub-section (2) shall be restored subject to such condition, if any, which the Council may deem fit to impose.

Procedure in inquiries.

42. For the purpose of any inquiry under the provisions of this Ordinance, the Council or any committee appointed under sub-section (1) of section 17 shall be deemed to be a court within the meaning of the Indian Evidence Act, 1872 and the Code of Civil Procedure 1908 and shall exercise all powers of a Commissioner appointed under the Public Servants(Inquiries) Act, 1850 and such inquiries shall be conducted, as far as may be, in accordance with the provisions of section 5 and sections 8 to 20 of the Public Servants (Inquiries) Act, 1850.

10 of 1872
4 of 1908

37 of 1850

Appeal against order of the Council.

43. Any person,—

- (a) whose application for enrolment in the State Register is rejected under section 38 or 41 ; or
- (b) whose entry in the State register is prohibited under section 40; or
- (c) whose name, from the State Register is removed ;

may, within ninety days of the order of rejection, prohibition or removal, as the case may be, appeal to the State Government and the decision of the State Government thereon shall be final.

Prohibition on practice except as provided in this Ordinance.

44. (1) Save as otherwise provided in this Ordinance, no person shall practise or hold himself out, whether directly or indirectly, as practicing habitually for personal as a paramedical practitioner within the State.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall be punishable with imprisonment which may extend to six months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.

Prohibition of awarding degree in certain cases.

45. (1) Where the Council on its own motion or on any representation received or otherwise is satisfied that any of person or para-medical institution has contravened all or any of the provisions of this Ordinance or the rules or regulations made or orders issued thereunder, it may, with the previous approval of the State Government, and subject to such conditions as it may think fit to impose,—

- (a) in the case of the first contravention, prohibit the paramedical institution concerned from presenting such students in relation to which the contravention has been made to any University or medical institution for taking any examination which would enable such students to qualify themselves for the award of any recognised medical qualification ; and

- (b) in the case of any second or subsequent contravention take such action under this Ordinance as it may consider necessary including action to prohibit the paramedical institution concerned from making any further admission of students :

Provided that no such order shall be passed by the Council unless the para-medical institution and the students concerned have been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) A copy of any order passed by the Council under sub-section (1), shall be communicated to the paramedical institution and the student concerned and a copy thereof shall simultaneously be forwarded to the University or paramedical institution concerned.

(3) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, an order passed by the Council under sub-section (1) and communicated to the University or paramedical institution under sub-section (2) shall be final and binding on the said University or paramedical institution.

(4) Any paramedical qualification granted to any student of such para-medical institution on the basis of any examination or other test held after the date of communication of the order to the University or paramedical institution under sub-section (2) shall cease to be a recognised paramedical qualification in relation to such student for the purposes of this Ordinance.

(5) Where an order has been passed by the Council under sub-section (1) in relation to any paramedical institution, the State Government may on its own motion or on any representation received by it, if it is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the interest of the students of such paramedical institution, take such steps as may be considered necessary to safeguard the interest of students studying in such paramedical institutions.

46. (1) Notwithstanding anything contained in this Ordinance or any other Law for time being in force paramedical institution established or courses started or increases of admission capacity made without prior permission of the State Government as required under section 19 of this Ordinance shall not be regularised by any authority whatsoever including the State Government.

Offences and penalties.

(2) Whoever contravenes the provisions of sub-section (1) shall not be eligible for any permission under section 19. This disqualification shall remain in force for a period of five years from the date the violation of section 19 is established.

(3) In case any approved or recognised paramedical institution starts a course and admits students without the prior permission of the State Government, the approved admission capacity of such institution in all its approved courses shall be reduced by 25% and such institution shall not be allowed to admit any student against the management or Non Resident Indian quota in the next academic year.

Penalty for
contraven-
tion of
sections 19,
20, 21, 27
or 39.

47. (1) Whoever contravenes the provisions of sections 19, 20, 21, 27 or 39 shall without prejudice to the provisions of section 45 of this Ordinance be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years and with fine which may extend to five lacs rupees but shall not be less than fifty thousand rupees.

(2) Where a conviction is made under sub-section (1), the court may in addition to awarding any punishment under that sub-section, by order in writing, require the paramedical institution or any other person convicted to refund the money so collected in excess to the person from whom it was collected within such period as may be specified in the order.

Offences by
companies.

48. (1) Where an offence under this Ordinance has been committed by a company every person who at the time the offence was committed, was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Ordinance has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary or other officer of the company, as the case may be shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.—For the purpose of this section:—

(a) “company” means any body corporate and includes a firm, institution, a society, a trust or other association of individual; and

(b) “Director” in relation to a firm means a person in the firm.

Punishment
for dis-
honest use
of certi-
ficate.

49. Any person who—

(a) dishonestly makes use of any certificate of registration granted under this Ordinance; or

(b) procures or attempts to procure registration under the provisions of this Ordinance by making or producing or causing to be made or produced any false or fraudulent declaration, certificate or representation whether in writing or otherwise ; or

(c) wilfully makes or causes to be made any false representation in any matter relating to the certificate of registration issued under the provisions of this Ordinance ;

shall on conviction, be punished with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to twenty thousand rupees but shall not be less than five thousand rupees or with both.

50. The Council shall furnish such reports, copies of its minutes, abstracts of its accounts and other information to the State Government as the State Government may require.

Information to be furnished by the Council.

51. (1) No court shall take cognizance of an offence punishable under this Ordinance except upon a complaint, in writing, made by the Registrar or any other officer authorised by the Council in this behalf, by a general or special order.

Cognizance of offence.

(2) No court inferior to that of a Magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Ordinance.

52. If at any time it appears to the State Government that Council has failed to exercise or has exceeded or abused any of the powers conferred, or has failed to perform any of the duties imposed, upon it by or under this Ordinance, the State Government may, if it considers such failure, excess or abuse to be of a serious character, notify the particulars thereof to the Council, requiring it to remedy such failure, excess or abuse within such period as may be specified in the notice and if the Council fails to remedy such failure, excess or abuse within specified period the State Government may dissolve the Council and cause all or any of the powers and the duties of the Council to be exercised and performed by any other Officer authorised by the State Government in this behalf, by order for such period not exceeding six months and shall take steps to bring into existence a new Council.

Control by State Government.

53. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette and after previous publication, make rules for carrying out the purposes of this Ordinance.

Power to make rules.

(2) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session for a total period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, the Assembly makes any modification in the rule or decides that the rules should not be made, the rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of any thing previously done under that rule.

54. (1) The Council may, with the previous approval of the State Government and subject to rules made under section 45, may by notification in the Official Gazette, make regulations to carry out purposes of this Ordinance, and without prejudice to the generality of foregoing power, such regulations may, provide for:—

Power to make regulations.

- (a) the management of the property of the Council and the maintenance and audit of its account;
- (b) the manner of election of members of the Council;
- (c) the powers and duties of the President and Vice-President;
- (d) the mode of appointment of Committees, the summoning and holding of meetings and the conduct of business of such Committees.

- (e) the travelling and other allowances payable to the Non-Official Members of the Council;
 - (f) the manner to hear and decide appeals from the decision of the Registrar under clause (b) of Sub-section (2) of section 18;
 - (g) the code of ethics for regulating the professional conduct under clause (c) of sub-section (2) of section 18 ;
 - (h) the qualification, the conditions of service and pay scales of the Registrar and other officers and servants under sub-section(3) of section 32;
 - (i) the manner of revision of State Register under sub-section (1) of section 33 ; and
 - (j) the form of State Register under sub-section (2) of section 38;
- (2) The State Government on receipt of regulations for approval, may approve the same without any modifications or with modifications as it may think fit or return to the Council for reconsideration.

SCHEDULE

PARAMEDICAL QUALIFICATIONS

[See section 2 (g)]

1. Physiotherapy/Occupational thereapy course.
2. Speech Therapy Course.
3. Audiologist.
4. Laboratory Technician (various types).
5. X-ray Technicians/Radiographer.
6. B. C. G. Technician.
7. Cyto Technician.
8. Ortho Technicians.
9. Mould room Technician.
10. Gamma Camera Technician.
11. Orthotic Technicians.
12. Optometrist.
13. Orthotic and contact lens.
14. E. C. G. Technician.
15. Ultra Sound.
16. Angiography.
17. Operation Theatre Technician.
18. Degree, Diploma and Certificate in Human Nutrition.
19. Dialysis Therapy Technician.
20. Insulation Therapy Technician.
21. Health Inspector Course.
22. Hospital Medical record science.
23. Compounder(Allopathy, Ayurvedic, Unani and Homoeopathy).
24. Compounder in Biochemic system of medicine.
25. Diploma in Clinical Biochemistry.
26. Microbiology.
27. Pathology.
28. Optometri refraction.
29. Paramedical Ophthalmic Assistant.
30. Perfusionist/Cardiac Surgery Technician.
31. Cath, Lab. Technician.
32. Dental Hygienist/Dental Machenic.
33. Male Health Worker.
34. Female Health Worker.